



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 391]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 12, 1979/अग्रहायण 21, 1901

No. 391]

NEW DELHI, WEDNESDAY DECEMBER 12, 1979/AGRAHAYANA 21, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1979

सं० का० नि० 688(अ).—राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई निम्न-लिखित उद्घोषणा सर्वनाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है:—

यतः मुझे, भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को अगम राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है, और इस रिपोर्ट तथा मुझे प्राप्त अन्य सूचना पर विचार करने के बाद मेरा समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें राज्य का शासन भारत के संविधान (जिसे इसमें इसके पश्चात् "संविधान" कहा गया है) के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है;

अतः अब मैं, संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा उस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एनर्वादा उद्घोषणा करता हूँ कि मैं:—

(क) उक्त राज्य की सरकार के सभी कृत्य और इस राज्य के राज्यपाल में निहित, तथा उनके द्वारा प्रयोज्य सभी शक्तियाँ, भारत के राष्ट्रपति के रूप में स्वयं संभालता हूँ;

(ख) पारित करना हूँ कि उक्त राज्य के विधान मंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा या उनके प्राधिकार के अन्तर्गत प्रयोज्य होंगी; और

(ग) निम्नलिखित आन्तरिक और पारिणामिक उपबंध करना हूँ जो इस उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए मुझे आवश्यक या वांछनीय प्रगति होते हैं; अर्थात्:—

(i) इस उद्घोषणा के उपर्युक्त खंड (क) के आधार पर संसद द्वारा संभाले गए कृत्यों और शक्तियों का प्रयोग करने में, मेरे लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में उस सीमा तक जिस तक मैं ठीक समझूँ उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करना विधिवत होगा;

(ii) उक्त राज्य के संसद में संविधान के निम्नलिखित उपबंधों के प्रयोजन की एनर्वादा निर्दिष्ट किया जाता है, अर्थात्:—

अनुच्छेद 3 के परन्तुक का उक्त भाग जितने का संबंध राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विधान मंडल को निवेश करने से है;

अनुच्छेद 151 के खंड (2) का उक्त भाग जितने का संबंध भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों को राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखे जाने से है; अनुच्छेद 163 और 164;

अनुच्छेद 166 के खंड (3) का उक्त भाग जितने का संबंध राज्य सरकार के कार्य के मंत्रियों के बीच बंटवारे से है;

अनुच्छेद 167 और 169;

अनुच्छेद 174 का खंड (1) अनुच्छेद 175, 176, और 177;

अनुच्छेद 179 का खंड (स) और उस अनुच्छेद का प्रथम परन्तुक;

अनुच्छेद 181, 188, 189, 193, 194, 196 और 198;

अनुच्छेद 199 का खंड (3) और खंड (4);

अनुच्छेद 208 से 211 (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं);

अनुच्छेद 213 के खंड (1) का परन्तुक और खंड (3) का परन्तुक; और

अनुच्छेद 323 के खंड (2) का उतना भाग जितने का संबंध ज्ञापन सहित रिपोर्ट को राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखे जाने से है;

- (iii) संविधान में राज्यपाल के प्रति किसी निदेश का अर्थ उस राज्य के संबंध में राष्ट्रपति के प्रति निदेश लगाया जाएगा और उसमें राज्य के अधीन मंडल या विधान सभा के प्रति किसी निदेश का, जहाँ तक उसका संबंध उनके कृत्यों और उनकी शक्तियों से है, अर्थ, जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, संसद के प्रति निदेश लगाया जाएगा और विधिगततया अनुच्छेद 213 में राज्यपाल और राज्य के विधान मंडल या उसके सदस्यों के प्रति निदेशों का अर्थ, क्रमशः राष्ट्रपति और संसद या उसके सदस्यों के प्रति निदेश लगाया जाएगा;

परन्तु इसमें कोई बात अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155 से लेकर अनुच्छेद 159 तक (जिसमें या दोनों सम्मिलित हैं), अनुच्छेद 299 और अनुच्छेद 361 तथा द्वितीय अनुसूची के पैरा 1 से लेकर पैरा 4 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं) के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी और न राष्ट्रपति को उस खंड के उपखंड (i) के अधीन उस सीमा तक जहाँ तक वह ठीक समझे उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करने से निवारित करेगी;

- (iv) संविधान में राज्य के विधान मंडल के या एतद्द्वारा बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निर्देश का ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो उसके अन्तर्गत इस उद्घोषणा के आधार पर संसद द्वारा या राष्ट्रपति या संविधान के अनुच्छेद 357 के खंड (1) के उपखंड (क) और असम साधारण खंड अधिनियम, 1915 (1915 का असम अधिनियम 2) जैसा कि वह असम राज्य में लागू है, में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा राज्य के विधान मंडल की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति निर्देश है, और साधारण खंड अधिनियम 1897 (1897 का 10) का उतना भाग जितना राज्य विधियों पर लागू है, ऐसे किसी अधिनियम या विधि के बारे में ऐसे प्रभावी होगा मानो यह उस राज्य के विधान मंडल का अधिनियम हो।

[सं० 5/11013/5/79 सी. एस. आर.]

नई दिल्ली,

12 दिसम्बर, 1979

नीलम संजीव रेड्डी

राष्ट्रपति

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 1979

G.S.R. 688(E).—The following Proclamation by the President is published for general information:—

Whereas, I, Neelam Sanjiva Reddy, President of India have received a report from the Governor of the State of Assam and after considering the report and other information received by me, I am satisfied that a situation has arisen in

which the Government of that State cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India (hereinafter referred to as "the Constitution");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by article 356 of the Constitution and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby proclaim that I—

- assume to myself as President of India all functions of the Government of the said State and all powers vested in or exercisable by the Governor of that State;
- declare that the powers of the Legislature of the said State shall be exercisable by or under the authority of Parliament; and
- make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary or desirable for giving effect to the objects of this Proclamation, namely:—

- in the exercise of the functions and powers assumed to myself by virtue of clause (a) of this Proclamation as aforesaid, it shall be lawful for me as President of India to act to such extent as I think fit through the Governor of the said State;

- the operation of the following provisions of the Constitution in relation to that State is hereby suspended, namely:—

so much of the proviso to article 3 as relates to the reference by the President to the Legislature of the State;

so much of clause (2) of article 151 as relates to the laying before the Legislature of the State of the reports submitted to the Governor by the Comptroller and Auditor-General of India;

articles 163 and 164;

so much of clause (3) of article 166 as relates to the allocation among the Ministers of the business of the Government of the State;

articles 167 and 169;

clause (1) of article 174; articles 175, 176 and 177; clause (c) of article 179 and the first proviso thereto; articles 181, 188, 189, 193, 194, 196 and 198;

clauses (3) and (4) of article 199; articles 208 to 211 (both inclusive);

the proviso to clause (1) and the proviso to clause (3) of article 213; and

so much of clause (2) of article 323 as relates to the laying of the report with a memorandum before the Legislature of the State;

- any reference in the Constitution to the Governor shall, in relation to the said State, be construed as a reference to the President, and any reference therein to the Legislature of the State or the Houses thereof, shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed, unless the context otherwise requires, as a reference to Parliament, and in particular, references in article 213 to the Governor and the Legislature of the State or the Houses thereof, shall be construed as references to the President and to Parliament or the Houses thereof respectively;

Provided that nothing herein shall affect the provisions of article 153, articles 155 to 159 (both inclusive); article 299 and article 61 and paragraphs 1 to 4 (both inclusive) of the Second Schedule or prevent the President from acting under sub-clause (i) of this clause to such extent as he thinks fit through the Governor of the said State;

- any reference in the Constitution to Acts or laws of or made by the Legislature of the State shall be construed as including a reference to Acts or laws made, in exercise of the powers of the Legislature of the State, by Parliament by virtue of this Proclamation, or by the President or other authority referred to in sub-clause (a) of clause (1) of article 357 of the Constitution and the Assam General Clauses Act 1915 (Assam Act 2 of 1915) as in force in the State of Assam and so much of the

General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) as applies to State laws, shall have effect in relation to any such Act or law, as if it were in Act of the Legislature of the State.

ORDER

New Delhi, the 12th December, 1979

New Delhi;

The 12th December, 1979.

[No. 5/11013/5/79-CSR]

NEELAM SANJIVA REDDY,
President

प्रवेश

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1979

सां. कां. निं. 689(प्र) :—राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है :—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन मेरे द्वारा आज दिसम्बर, 1979 के बारहवें दिन जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) के उपखंड (1) का अनुसरण करते हुए मैं एतद्वारा निवेश देता हूँ कि असम राज्य सरकार के सभी कृत्य और संविधान के अधीन या उस राज्य में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उस राज्य के राज्यपाल में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियाँ, जिनको राष्ट्रपति ने उक्त उद्घोषणा के खंड (क) के आधार पर स्वयं संभाल लिया है, राष्ट्रपति के अधीक्षण, निवेशन और नियंत्रण के अध्याधीन रहते हुए, उक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी।

नई दिल्ली,
12 दिसम्बर, 1979

नीलम संजीव रेड्डी
राष्ट्रपति

[सं. 5/11013/5/79-सी. एस. आर.]

एम. एल. कम्पानी, अपर सचिव

G.S.R. 689(E).—The following Order by the President is published for general information :—

In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of the Proclamation issued on this the 12th day of December, 1979, by me under article 356 of the Constitution of India, I hereby direct that all the functions of the Government of the State of Assam and all the powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution or under any law in force in that State, which have been assumed by the President by virtue of clause (a) of the said Proclamation shall, subject to the superintendence, direction and control of the President, be exercisable also by the Governor of the said State.

New Delhi;

The 12th December, 1979.

NEELAM SANJIVA REDDY,
President

[F. No. V/11013/5/79-CSR]

M. L. KAMPANI, Addl. Secy.

